उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव की प्रेस–वार्ता
दिनांक – 21 अगस्त 2024

जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांगों को पूरा करने तथा राज्य में शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने मैं नगरीय निकायों के लिए 450 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा करता हूं – इसके साथ ही नगरीय निकायों में 15वें वित्त आयोग के तहत अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए जल्दी ही 450 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इस तरह से प्रदेश के शहरों में नए विकास कार्यों और नई सुविधाएं विकसित करने के लिए कुल 900 करोड़ रुपए नगरीय निकायों को मिलेंगे।

जनसमस्या निवारण पखवाड़ा

- नागरिकों की समस्याएं दूर करने और उनकी जरुरतों को समझने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विगत 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। शहरी नागरिकों को इसका बेहतर प्रतिसाद मिला है। मैंने खुद कई जनसमस्या निवारण शिविरों में पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी थीं और नागरिकों से मुलाकात की थी। मैंने सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को यथासंभव मौके पर ही निराकृत करने के निर्देश दिए थे।
- पखवाड़ा के दौरान प्रदेश भर में आयोजित शिविरों में करीब एक लाख 30 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 37 प्रतिशत यानि 48 हजार आवेदनों का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया है। दूसरे विभागों से संबंधित आवेदनों को संबंधित विभागों को प्रेषित करने के बाद शेष आवेदनों का परीक्षण कर शीघ्र निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।
- लोगों की जरूरतों और मांगों से संबंधित निर्माण कार्य से जुड़े कार्य बारिश की वजह से नहीं हो पाए हैं। बरसात के बाद ये कार्य तेजी से पूर्ण किए जाएंगे। शहरों में आयोजित जनसमस्या निवारण पखवाड़ा की यह बड़ी सफलता होगी।
- प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिए जारी की जा रही 450 करोड़ रुपए की राशि से शिविरों में प्राप्त निर्माण संबंधी काम किए जाएंगे। शहरी आबादी की बड़ी मांग इससे पूरी हो जाएगी।

- जनसमस्या निवारण शिविरों में प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 17 हजार 512 आवेदन मिले जिनमें से 1181 का त्वरित निराकरण किया गया। शिविर स्थल पर ही हितग्राहियों को पात्रतानुसार नए आवास की स्वीकृति, आवास आवेदन की त्रुटियों का निराकरण, किस्त का भुगतान तथा अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में कार्यवाही की गई।
- पेयजल समस्या से जुड़े 5573 आवेदनों में से 1233 का शिविर में ही समाधान किया गया। इस दौरान लोगों की मांग एवं शिकायत के अनुसार नए नल कनेक्शन, पाइपलाइन का विस्तार, पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति संबंधी समस्याओं को निराकृत किया गया।
- जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण, नाली सफाई, पानी निकासी तथा साफ–सफाई से संबंधित शिकायतों का तत्परता से निराकरण किया गया। नगरीय निकायों की टीम द्वारा कचरा एकत्रीकरण एवं उठाव से संबंधित 1796 आवेदनों में से 1127 को शिविर स्थल पर ही निराकृत किया गया।
- शिविरों में निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आ रही समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण कर पेंशन की राशि प्रदान की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधी प्राप्त 2263 आवेदनों में से निकाय स्तर के 570 आवेदनों को तत्काल निराकृत किया गया। शेष आवेदनों के परीक्षण की कार्यवाही जारी है।
- नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में सड़क व नाली मरम्मत तथा निर्माण कार्य से जुड़े 17 हजार 655 आवेदनों में से 809 आवेदनों को तत्काल स्वीकृत कर सड़क और नाली मरम्मत के कार्य किए गए। शेष मांगों के अनुरूप नई नाली और सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। नवीन निर्माण कार्यों से संबंधित प्रस्ताव स्थल चयन तथा जांच के उपरांत निकाय के माध्यम से शासन को भेजे जाएंगे।
- जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान शिविर स्थल पर ही संपत्ति कर के भुगतान की सुविधा मुहैया कराई जा रही थी। नए भवनों के संपत्ति कर एवं संपत्ति निर्धारण संबंधी शिकायतों के निराकरण के साथ ही इनसे संबंधित 642 आवेदनों में से 380 को मौके पर ही निराकृत किया गया।

- शिविर स्थल पर ही संपत्ति के नामांतरण, नए भवन निर्माण की स्वीकृति तथा नियमितीकरण संबंधी मांगों का यथासंभव निराकरण किया गया। इनसे जुड़े 1117 आवेदनों में से 58 का त्वरित निराकरण किया गया। शेष आवेदन जिला कार्यालय या नगर निवेश से संबंधित होने के कारण इन विभागों के समन्वय से निराकृत किए जाएंगे।
- वार्डवार आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में नए राशन कार्ड का वितरण, राशन कार्ड में त्रुटि सुधार एवं पात्रतानुसार बीपीएल/एपीएल राशन कार्ड बनाकर आवेदकों को दिए गए। राशन कार्ड से संबंधित 21 हजार 701 आवेदनों में से 11 हजार 541 मौके पर ही निराकृत किए गए। शेष आवेदनों का परीक्षण कर शीघ्र समाधान किया जाएगा।
- स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शिविर स्थल पर ही वार्डवासियों के प्राथमिक उपचार और रक्त परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। पखवाड़ा के दौरान 9701 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर जरूरी उपचार मुहैया कराया गया। शिविरों में 7613 आयुष्मान कार्ड भी बनाकर वितरित किए गए।
- भूमि विवाद एवं राजस्व प्रकरणों के 14 हजार 80 आवेदनों में से 3000 आवेदनों का निराकरण भी पखवाड़ा के दौरान किया गया। शिविरों में बिजली, स्ट्रीट लाइट, मवेशी, आवारा कुत्तों, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, सड़क बाधा इत्यादि से संबंधित 30 हजार 489 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से निकाय स्तर के 11 हजार 146 आवेदनों का त्वरित समाधान किया गया। शेष आवेदन अन्य विभागों से संबंधित होने के कारण संबंधित विभागों को निराकरण के लिए प्रेषित किए गए हैं।
- **प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के विकास और नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सक्रियता से काम कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के ध्येय को धरातल पर उतारते हुए हम बिना किसी भेदभाव के सभी नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करा रहे हैं।**
- **मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार गठित होने के शुरुआती 8 महीनों में ही नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 1250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अधोसंरचना विकास के साथ जनसुविधाएं विकसित करने के काम किए जा रहे हैं।**

- पिछले 8 महीनों में जारी 1250 करोड़ रुपए और नगरीय निकायों को जल्द मिलने वाली 900 करोड़ रुपए को मिलाकर हमारी सरकार द्वारा शहरों के विकास के लिए मुहैया कराई जाने वाली राशि 2150 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के पास राशि की कमी नहीं है। सभी नगरीय निकायों के लिए उनकी मांगों और जरुरतों के मुताबिक राशि स्वीकृत की जा रही है।

——00——